THE MINISTER OF STATE (IN DEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI K. RAMAMURTHY): (a) and (b) The working of the Employee's State Insurance Scheme and the Employees Provident Funds Scheme are being reviewed periodically by High Powered Tripartite Committee consisting of representatives of the Central Organisations of employers and employees and the Government. The working of the two schemes were last reviewed in early eighties.

(c) The ESI Act was last amended in 1989. *At* present, there is no proposal for further amendment of the Act.

(d) The Provident Fund Accounts in Andhra Pradesh, Bihar Delhi, Karnataka, Madhva Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan and Tamil Nadu have so far been computerised. The accounts in the remaining resions are likely to be computerised by the end of 1991-92.

कृषि को उद्योग का दर्जा

414. श्री अब्दुल रहमान खान्चेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा देने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसकी विस्तृत योजना क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) भारत सरकार ने कृषि को उद्योग के रूप में घोषित करने से संबंधित मामलों का अध्ययन करने के लिए श्री भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया था । उक्त विषय पर समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

पटना-दिल्ली खण्ड में रेलों का विलम्ब से चलना

415. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) विगत तीन महीनों में अर्थात् मार्च, अप्रैल, मई 1991 में पटना-दिल्ली और दिल्ली-पटना के लिए गाड़िया कितने दिन समय से चली और कितने दिन विलम्ब से ;

(ख) गाड़ियों का विलम्ब से चलने का कारण क्या था ; और

(ग) क्या गाड़ियों को समय पर चलाने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलिलकार्जुन) : (क) इस अवधि के दौरान मगध एक्सप्रैस और श्रमजीवी एक्सप्रैस नई दिल्ली से क्रमश: 63 और 78 दिन और पटना से 12 और 43 दिन सही समय पर चली ।

(ख) मुख्यत: खतरे की जंजीर खींचे जाने, शरारती गतिविधियों, दुर्घटनाओं और उपस्करों की खराबी के कारण ये गाड़ियां विलम्ब से चलीं ;

(ग) जुलाई 91 के प्रथम 15 दिनों के दौरान एक अभियान चलाया गया है। इस अवधि के दौरान समयपालन में 4 से 5 प्रतिशत का सुधार आया है ।

बिहार के लिए सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

416 श्री शंकर दयाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की सिंचाई संबंधी कितनी परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास विचारार्थ पड़ी हुई हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार ने इन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है और उन परियोजनाओं को स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण

1. (क) तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है ।	6	9	राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना में अध्यधीन से परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार करके स्वीकृत किया गया ।
(ख) तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है परन्तु तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा आस्थगित की गई ।	2	—	परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत की गई किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार तथा दामोदर घाटी निगम के साथ अन्तर्-राज्यीय मुद्दों के हल न होने के कारण विचार करना आस्थगित कर दिया गया ।
2. तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन है ।	5	5	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भेजी गई टिप्पणियों पर राज्य सरकार द्वारा अनुपालना [illegible] नी है।
जोड़	13	14	